

>

Title : The Minister of External Affairs made a statement regarding conduct of anti-piracy operations in the gulf of Aden and off the coast of Somalia.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S.M. KRISHNA): The Cabinet Committee on Security met today and considered proposals with regard to conduct of anti-piracy operations in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia. The Committee approved a series of measures which will be taken by the Government of India to address the legal, administrative and operational aspects of combating piracy. A broad policy framework covering all these aspects was approved. This would involve actions that would be taken in the medium and long term by the Ministries of Shipping, External Affairs and Defence

The Committee also specifically considered the immediate situation arising out from holding of Indian hostages by pirates. It noted that as of now 53 Indian seafarers remain in captivity on five different ships. The Committee expressed its sympathy with the families of the hostages, and decided that the Government would take all appropriate action to safeguard their welfare. It approved the following immediate steps :-

Intensify diplomatic efforts through consultations with the Governments of Egypt and the UAE where the owners of concerned vessels reside, as well as with the Governments of other nationalities who are also being held as hostages and intensifying diplomatic efforts both at the multilateral level and within the framework of the United Nations.

Stepping up of contacts with the owners of the vessels concerned.

Establishing of Inter-ministerial Group under the chairmanship of the Cabinet Secretary. The Group will act as an apex forum at the Government of India level to monitor the early release of Indian ships or cargo or crew. The Group will also consider welfare measures necessitated after the release of hijacked Indian nationals.

Formulation of suitable standard operating procedures for the Indian Navy and coordination of the Indian Navy's activities with the Navies of friendly foreign countries in the Gulf of Aden. Thank you.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदेश): अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने समुद्री डकैती से संबंधित एक प्रस्ताव सदन में रखा है। भारतीय बंधकों के परिवारजन कल आपको मिलने आए थे, आपने उनकी कहानी सुनी और उनकी कहानी इतनी दर्दनाक थी कि आप सुनकर स्वयं व्यथित हो गयीं। उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, उन्होंने भी उनकी पीड़ा से स्वयं को संबद्ध करते हुए यह आश्वासन दिया था कि सरकार हर वह संभव प्रयत्न करेगी जिससे भारतीय बंधक सुरक्षित घर वापस लौट आएंगे। मैं धन्यवादी हूँ कि उसके 24 घंटे से भी पहले विदेश मंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिवयोरिटी की एक मीटिंग करके जो उपाय बताए गए, उनको सदन के सामने रखा है। मैं विदेश मंत्री से केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि जो उपाय यहां होने हैं, उनका आपने जिक्र किया है।

लेकिन यूएन सिवयोरिटी कौंसिल में एंटी पायरेसी पर रिजोल्यूशन पर रिजोल्यूशन पास हुए हैं, वहां मेकेनिज्म बने हुए हैं। इंटरनेट पर देखने से पता चला कि वहां पर मेकेनिज्म हैं, वहां एक इंटरनेशनल फंड भी है, इंटरनेशनल ट्रस्ट भी है। आपने जो यहां बातें कही हैं, वे तो आप करेंगे, डिप्लोमैटिक एफर्ट्स भी आप करिए, ओनर्स से भी आपने कहा है कि सम्बन्ध स्थापित करेंगे। लेकिन हमें इस रिजोल्यूशन के सम्बन्ध में बने हुए जो मेकेनिज्म हैं, उनका भी सहारा लेना चाहिए, ताकि जैसे अभी आप सात महीने के बाद एक शिप के बारे में कर रहे हैं, एक साल के बाद दूसरे शिप के बारे में कर रहे हैं, बाकी शिप्स ढाई-ढाई साल से पड़े हैं, वह इंटरनेशनल मेकेनिज्म तुरंत उसमें कार्यरत हो जाए और इतने-इतने वर्षों तक हमारे बच्चों को वहां न रहना पड़े। मेरा यह सुझाव है, अगर आप इस सुझाव को मान लेंगे तो साल-साल तक, दो-दो साल तक लोगों को अपने बच्चों के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपने कल और आज में इतना किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।